



ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 मार्च, 2020

मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी



जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 का आम बजट प्रस्तुत किया। बजट में जीरो बजट फार्मिंग, किसानों की आय दोगुनी करने, विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, स्टार्टअप और स्वरोजगार से रोजगार सृजन करने, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने और नई शिक्षा नीति को जल्द लागू करने की बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

आयुष्मान योजना का बजट बढ़ाने, सामाजिक कल्याण को अहमियत देने तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने का भी वादा बजट में शामिल है। बजट में कई सुधार भी सामने आए हैं, जो देश के

आर्थिक और बहुआयामी विकास को नई दिशा देंगे।

मेरा मानना रहा है कि कुल मिलाकर यह बजट तभी अच्छा कहा जा सकेगा, जब घोषणाएं वास्तविक रूप से धरातल पर उतरें और उनका समय पर सही क्रियान्वयन हो। इसके लिए समय का निर्धारण, ठोस नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधार बेहद जरूरी है। ध्यान यह भी रखना होगा कि महत्वपूर्ण घोषणाएं कहीं कागजी पुलिन्दा बन कर न रह जाएं।

जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो, यह सुशासन का मूल मंत्र होना चाहिए। आम ग्रामीण बजट के आंकड़ों को सही रूप से समझ नहीं पाता। इसलिए 'ग्राम गदर' में समय-समय पर गांवों से सम्बन्धित बजट घोषणाओं को सरल व तार्किक रूप में प्रकाशित किया जाता रहेगा, ताकि ग्रामीणजन इन घोषणाओं के अमल पर पैनी नजर रखकर लाभान्वित हो सकें।



खेती और किसानों को दी बजट में ज्यादा अहमियत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा करके उनके जीवन में उजाला कर चुकी है। वर्ष 2020-21 के बजट में किसानों के लिए 15 लाख करोड़ रुपए के कृषि ऋण का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री-किसान के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा। जीरो बजट, जैविक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से ऑनलाइन राष्ट्रीय पोर्टल को मजबूत बनाया जाएगा। बजट में गांव और किसानों के लिए 16 सूत्री कार्य योजना की घोषणा कर किसान की तकदीर बदलने का सपना देखा गया है। पंचायत स्तर पर कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। भंडारण क्षमता बढ़ने से कृषि उत्पादों को देर तक संभाल कर रख पाना संभव होगा।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार कर इसके दायरे में 20 लाख किसानों को और कवर किया जाएगा। सरकार 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पम्प लगाने में मदद करेगी। किसान बंजर भूमि में सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकेंगे। इससे अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बनेगा। वे अतिरिक्त पैदा हुई बिजली को बेच भी सकेंगे। जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के जल्द परिवहन के लिए 'वातानुकूलित किसान रेल' सेवा की शुरुआत होगी। बहुस्तरीय फसल उगाने, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सौर पंपों के इस्तेमाल तथा सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाया जाएगा।

स्वास्थ्य: चलेगा फिट इंडिया अभियान

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में 69 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया है। टिटनेस, पोलियो, रोजावायरस जैसे रोगों की रोकथाम के लिए 5 नए टीकों की घोषणा की गई है। जीवन शैली में सुधार के लिए फिट इंडिया अभियान चलाने की भी योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अलग से 6400 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अन्तर्गत 20 हजार से अधिक अस्पताल जुड़े हुए हैं। स्कीम के तहत टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में और नए अस्पताल खोले जाएंगे।

आयुष्मान भारत में पीपीपी मॉडल के तहत ज्यादा निवेश किया जाएगा। वहीं, मेडिकल उपकरण पर कर लगाया गया है। इससे प्राप्त राशियों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। हर जिले में आयुष्मान भारत का अस्पताल बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 'टी.बी. हारेगा देश जीतेगा' अभियान शुरू किया गया है। इसके जरिए साल 2025 तक टी.बी. समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12 हजार 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 4 हजार 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य रोग रहित भारत बनाना है।



'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार, 2019

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ति-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 38 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ट पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2019 का विषय जिस पर उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह है:

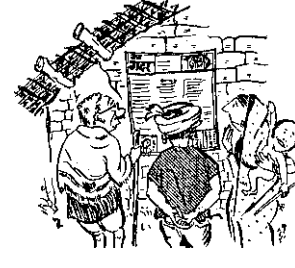
'प्रदेश में ग्रामीण रोजगार की स्थिति'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित।
- टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2019 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2020 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।
कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स), डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोन: 0141-2282821, फैक्स: 0141-2282485, 4015395 ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org



महिला व बाल विकास पर फोकस

बजट में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए 28 हजार 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह राशि महिलाओं के विकास से संबंधित विशिष्ट कार्यक्रम और योजनाओं पर खर्च होगी। महिला एवं बाल कुपोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए बजट में 35 हजार 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 करोड़ घरों तक पहुंचने के लिए स्मार्ट फोन दिए गए हैं। ताकि पोषण आहार से जुड़ी जानकारी का ब्योरा जुटा सकें।

बजट में महिला स्वयं सहायता समूहों के हाथों में भंडारण व्यवस्था होगी। यह उन्हें 'धान्यलक्ष्मी' का स्थान देने का प्रयास है। उनके द्वारा संचालित किए जाने वाली ग्राम भंडार स्कीम से गांव के किसानों को फायदा मिलेगा। इस नई योजना में महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

हॉर्टिकल्चर सेक्टर में 'वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट' योजना पर फोकस किया जाएगा, ताकि मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। जन-धन बैंक खाते वाली स्वयं सहायता समूह की हर महिला सदस्य को मुद्रा योजना के तहत एक लाख तक के लोन की पात्रता को जारी रखा गया है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' मिशन के नतीजे सुखद रहे हैं। बजट में इस मिशन पर और ज्यादा जोर दिया गया है।

बजट की अन्य प्रमुख घोषणाएं

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बजट में 85 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है, इसके अलावा आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए बहुत-सी नई सुविधाओं की घोषणा की गई है। वरिष्ठ नागरिकों और निःशक्तों के लिए बजट में 9,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की जाएगी।

पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुओं में होने वाली ब्रूसिलोसिस और पीपीआर बीमारी को वर्ष 2025 तक खत्म करने का वादा किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज वर्तमान में 30 प्रतिशत को बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 से बढ़ाकर 108 मिलियन मिट्रिक टन करने का लक्ष्य है।

नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द

बजट में नई शिक्षा नीति को इस बार फिर से दोहराया गया है। लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह कब अस्तित्व में आएगी। वित्त मंत्री ने कहा इसके बेहतर प्रबंधन के लिए अधिक फंड की आवश्यकता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को मंजूरी देने की बात भी कही गई है। उच्चतर शिक्षा को समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

शिक्षा की बेहतरी के लिए केंद्र ने 4 हजार 447 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया है। अब बजट में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा पर 99 हजार 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे स्कूल-कॉलेजों में बेहतर संसाधन मिल पाएंगे। राष्ट्रीय क्वांटस टेक्नोलॉजी मिशन में आठ हजार करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है।

जिला अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर जोड़ने का प्रस्ताव है। कौशल शिक्षा के लिए तीन हजार करोड़ का प्रावधान बताया है कि कौशल शिक्षा पर सरकार की प्राथमिकता है। इससे स्व-रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए भी पॉलिसी बनाई गई है।

जिला अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर जोड़ने का प्रस्ताव है। कौशल शिक्षा के लिए तीन हजार करोड़ का प्रावधान बताया है कि कौशल शिक्षा पर सरकार की प्राथमिकता है। इससे स्व-रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए भी पॉलिसी बनाई गई है।

राज्य विद्युत आयोग द्वारा टैरिफ में संशोधन

हाल ही में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगम कंपनियों के टैरिफ दरों में परिवर्तन के लिए आदेश और प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। हालांकि इस आदेश के अनुसार आयोग ने वितरण कंपनियों के टैरिफ दरों को बढ़ाने की याचिका को मान लिया है, लेकिन साथ ही वितरण कंपनियों को उपभोक्ताओं की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ कदम उठाने को भी कहा है।

आयोग ने ये आदेश दिया है कि तीनों डिस्कॉम 24/7 ग्राहक सहायता डेस्क की स्थापना करें जहां उपभोक्ता किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। ये सहायता डेस्क उपभोक्ताओं को प्रासंगिक जानकारी जैसे टैरिफ नियम, प्रदर्शन का मानक आदि के बारे में सूचना प्रदान करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण कंपनियां समय पर फाल्ट रिमुवल में अक्षम रही हैं। इसलिए वितरण कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली की फाल्ट रिमुवल टीम को तैयार करने के लिए भी कहा गया है, जो वर्तमान में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं।

इस टैरिफ आदेश के अनुसार अब सरकारी स्कूलों पर घरेलू वर्ग की दरें लागू होंगी जो पहले मिश्रित भार वर्ग में आते थे। हालांकि पहले से ही कुछ सरकारी स्कूल जानकारी या पहल के अभाव में मिश्रित भार की जगह गैर-घरेलू वर्ग की दरों पर भुगतान कर रहे थे और 'कट्स' द्वारा एक मुहिम चलाई गई जिसके द्वारा कुछ स्कूलों को मिश्रित भार वर्ग में स्थानांतरित किया गया था। अतः सारे सरकारी स्कूलों को इस परिवर्तन का ध्यान रखना जरूरी है।

अब खुद चुनना होगा आयकर स्लैब

अब करदाता को पुराने या नए आयकर स्लैब में से खुद को एक विकल्प चुनना होगा। उसे स्वयं गणित लगानी होगी कि उसके लिए पुराना विकल्प फायदेमंद रहेगा या नया विकल्प। अगर किसी की आय पांच लाख से ज्यादा नहीं है (कटौति और कर छूट का दावा करने के बाद आय) तो आयकर एक्ट की धारा 87ए के तहत 12,500 रुपए तक कर छूट मिलेगी। अर्थात् दोनों विकल्पों में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा।

आयकर को आसान बनाने के साथ रेट में भी कमी की गई है। बचत आधारित जीवनशैली वाले करदाताओं के लिए पुराना विकल्प मौजूद रहेगा। नया विकल्प लेने वालों अर्थात् ज्यादा खर्च करने वालों को पूर्व की तुलना में 5 से 10 फीसदी तक का कम कर चुकाना होगा।

बुनियादी ढांचे के विकास पर किया मंथन

बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए 103 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इससे शहरी और ग्रामीण विकास को बल मिलेगा और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर तेजी से काम किया जाएगा। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में यह स्कीम लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट में 22 हजार करोड़ रुपए पावर सेक्टर के लिए प्रस्तावित है। इससे सौर ऊर्जा सस्ती होगी। 100 फीसदी बिजली के स्मार्ट मीटर लगने हैं, जिससे बिजली खपत और बिल पर असर पड़ेगा। 2500 किमी राजमार्ग और 9 हजार किमी आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।

'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक	
फॉर्म-4 (नियम 8)	
'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक के स्वामित्व का विवरण और अन्य विवरणों में जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अंतिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-	
1. प्रकाशन का स्थान	जयपुर
2. प्रकाशन अवधि	मासिक
3. मुद्रक का नाम	भारतीय प्रिन्टर्स, जयपुर
नागरिकता	भारतीय
क्या विदेशी है	नहीं
4. प्रकाशक का नाम	प्रदीप सिंह महता
नागरिकता	भारतीय
क्या विदेशी है	नहीं
पता	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
5. सम्पादक का नाम	प्रदीप सिंह महता
नागरिकता	भारतीय
क्या विदेशी है	नहीं
पता	डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हैं तथा समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों।	एक यात्र स्वामी
प्रदीप सिंह महता एण्ड ट्रांस घोषणा करता है कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विवरण के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।	प्रदीप सिंह महता
	प्रकाशक के हस्ताक्षर